



तनाव कम करना वक्त की जरूरत

जहां इस्राइली मिसाइल ने गाजा में मीडियाकर्मियों के दफ्तरों को निशाना बनाया, वहीं फलस्तीनी हमले का शिकार बनने वालों में युवा हिंदुस्तानी नर्स सौम्या संतोष भी हैं, जो वहां जिंदगी बचाने का काम कर रही थीं।

मनीष वर्मा।।

इस्राइल और फलस्तीन के बीच पिछले एक हफ्ते से जारी भीषण गोलाबारी से चितित वैश्विक समुदाय ने ठीक ही अपील की है कि सबसे पहले दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने का उपाय किया जाए। हिंसा के इस ताजा दौर में उड़ते सौ से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, इसके बावजूद दोनों में से कोई भी पक्ष युद्धविराम के लिए तैयार नहीं दिख रहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने भी जोर देकर कहा कि वहां तत्काल तनाव कम करना वक्त की जरूरत है। इससे इनकार नहीं कि इस्राइल और फलस्तीन के बीच विवाद पुराना है और बीच-बीच में इनमें हिंसक झड़प भी होती रही है। लेकिन इस तरह की हिंसा वहां

2014 से नहीं हुई थी। जाहिर है, यह हिंसा जारी रही तो इसके और फैलने की आशंका बढ़ेगी। इसलिए यह वक्त इन सवालों में जाने का नहीं है कि हिंसा किसकी तरफ से क्यों शुरू हुई थी और इसके लिए दोनों पक्षों में से कौन कितना जिम्मेदार है।

अहम तथ्य यह है कि इस हिंसा की कीमत न केवल दोनों तरफ के बेकसूर नागरिक अपनी जान देकर चुका रहे हैं बल्कि वे लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं, जिनका दोनों पक्षों के बीच जारी विवाद से भी किसी तरह का कोई लेना-देना नहीं है। जहां इस्राइली मिसाइल ने गाजा में मीडियाकर्मियों के दफ्तरों को निशाना बनाया, वहीं फलस्तीनी

हमले का शिकार बनने वालों में युवा हिंदुस्तानी नर्स सौम्या संतोष भी हैं, जो वहां जिंदगी बचाने का काम कर रही थीं। बावजूद इसके दोनों में से कोई भी पक्ष हिंसा रोकने की तैयारी नहीं दिखा रहा तो यह साफ है कि मामला सिर्फ किसी खास कार्रवाई का जवाब देने या अपनी रक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करने का नहीं है। हिंसा का यह दौर जहां हमारा जैसे अतिवादी संगठन को फलस्तीनी समाज में अपनी पैठ बढ़ाने का मौका दे रहा है, वहीं अल्पमत में आ चुकी नेतृत्वाहू सरकार को अस्तित्व बचाने का आखिरी अवसर भी मुहैया करा रहा है। लेकिन जब दुनिया पहले से ही कोरोना वायरस



की भीषण चुनौती का सामना कर रही हो, तो ऐसे में हिंसा की इस चिंगारी के लिए दावानल बनने का मौका नहीं छोड़ा जा सकता।

बेशक यह विवाद पुराना है और दोनों में से किसी भी पक्ष को रातोंरात किसी खास फॉर्म्यूल पर सहमत कराना मुश्किल है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक यथास्थिति को बदलने की इकतरफा कोशिश न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए भी दोनों पक्षों में न्यूनतम विश्वास कायम करना जरूरी है। वह काम दोनों पक्षों के बीच बातचीत से ही हो सकता है। उम्मीद की जाए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपील के बाद अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का हस्तक्षेप दोनों पक्षों को इस ओर ले जाने में सफल होगा।

आकर्षण

अशोक वोहरा।

हमारा पूरा जीवन इस इच्छा में निकल जाता है कि हमें कहीं से एक योग्य गुरु मिल जाए जो हमारी सभी आध्यात्मिक शंकाओं को दूर कर सके। जब हम आध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तो उसका पहला चरण है उस परमेश्वर के प्रति आकर्षण और ऐसा आकर्षण जो आसपास की सभी भौतिक वस्तुओं से आपको दूर कर दे। आध्यात्म के दूसरे चरण में आप उसके बारे में खोजने निकलते हैं। जिसका साधन स्वाध्याय और सत्संग है। यहां सत्संग का अर्थ आध्यात्मिक बाजार में चल रहे सत्संगों से नहीं है। इस सत्संग का अर्थ अपने जैसे जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों से चर्चा करना है। ऐसे सत्संगों में एक दूसरे से चर्चा करने पर नित नए प्रश्न उठते हैं। किसी का उत्तर आपको मिल जाता है और किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिलता। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिलता वह प्रश्न आपके मस्तिष्क में घूमता रहता है।

धर्म-दर्शन



संपादकीय

स्ट्रैटिजिक पॉलिसी चाहिए

न्यूक्लियर वॉर के मामले में जो लॉजिक इस्तेमाल होता है, वही लॉजिक सायबर अटैक के मामले में भी है। दूसरा देश तभी सायबर वॉर से हिचकिचाएगा, जब उसे लगेगा कि आप भी हमला कर सकते हैं। यह वैसी बात नहीं कि बंदूक अमेरिका और राफल फ्रांस से खरीद लाए। यह सायबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन का मामला है। एक स्ट्रैटिजिक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। कहा जाता है कि हम सायबर युद्ध से बचाव की क्षमता बना रहे हैं। मेरा कहना है कि हमें हमले के लिए भी अपनी क्षमता बनानी होगी, लेकिन ऐसा कहना हमारे स्ट्रैटिजिक कल्चर में नहीं है। हालांकि हमले की क्षमता बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं। अगर आपको हैकर्स चाहिए, तो आज भारत में ढेरों मिल जाएंगे। यंगस्टर्स तो इस काम में माहिर हैं। ब्रिटेन का मुझे पता है। वहां ऐसे ही लोगों को रखा गया है। अगर आपको लगता है कि चीन के साथ सीमा पर जो लड़ाई चल रही है, वही असल लड़ाई है तो जान लीजिए कि 'ड्रैगन' ऐसे कभी नहीं लड़ता। वह दूसरे देश की कमजोरी पर हमला करता है। हमने जब दिखा दिया कि हम भी बॉर्डर पर खड़े हो सकते हैं, तो वह वहां पर क्यों लड़ाई करेगा? वह हमारी कमजोरी को ढूँढेगा और वहां हमला करेगा। और सायबर डिफेंस मामले में हम कमजोर हैं भी। हमारी सरकारी वेबसाइटें हैक हो जाती हैं, डेटा सेंटर्स हैक हो जाते हैं। भारत में लेकिन इस तरह का कोई प्रावधान ही नहीं। अभी बस इस बारे में सोचा ही जा रहा है। वैसे नीति बनाने वालों को अच्छे से पता है कि उनके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

भारत तो दो मोर्चों पर यह लड़ाई लड़ रहा है। कई चीजें चीन खुद नहीं करेगा, लेकिन उसकी ओर से वही काम पाकिस्तान कर देगा। इसलिए भारत का पाकिस्तान पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है।

पाक पर ज्यादा जोर

हर्ष वी पंत।।

पंद्रह देशों में काम करने वाले संगठन इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्ट्रैटिजिक स्टडी ने पाया है कि भारत की सारी सायबर ताकत पाकिस्तान के खिलाफ लग रही है, जबकि उस पर अधिक हमले चीन कर रहा है। इसमें दो बातें हैं। पहली, सामरिक तौर पर हमारा ध्यान बहुत पहले से पाकिस्तान पर रहा है। इसलिए हमारे इंस्टिट्यूट्स की नजर अभी भी पाकिस्तान पर है और इंस्टिट्यूट्स को बदलने में वक्त लगता है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान और चीन को अलग-अलग देखना गलत है। भारत तो दो मोर्चों पर यह लड़ाई लड़ रहा है। कई चीजें चीन खुद नहीं करेगा, लेकिन उसकी ओर से वही काम पाकिस्तान कर देगा। इसलिए भारत का पाकिस्तान पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। हालांकि मुझे लगता है कि पिछले साल गलवान की घटना के बाद से माइंडसेट बदल रहा है। हमने देखा है कि कैसे हर क्षेत्र में अब फोकस चीन पर है।

यह स्टडी आगे कहती है कि भारत की सायबर वॉर रणनीति में कई कमियां हैं। चीन और पाकिस्तान नॉर्मल स्टेट नहीं हैं। एक तरफ है पाकिस्तान, जहां सेना बेहद ताकतवर है। उसकी विदेश नीति में सेना की प्राथमिकताएं दिखती हैं। दूसरी तरफ है चीन। वहां क्या चलता है, इस



बारे में हमें क्या, अमेरिका जैसे देश तक को पता नहीं चल पाता। चीन में भी पिछले कुछ बरसों से सेना का रोल बढ़ा है। जब आपके दोनों तरफ दो ऐसे मुल्क हों, तो स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाती है। इन दोनों पड़ोसी देशों में सेना गैर-परंपरागत तौर-तरीके इस्तेमाल कर रही है, मसलन ग्रे जोन ऑपरेशन। इसे ऐसे समझें कि पाकिस्तानी सेना सीधे भारतीय सेना के सामने नहीं आ सकती, इसलिए वह आतंकवाद को प्रायोजित करती है। यही ग्रे जोन ऑपरेशन है।

इस मामले में चीन का हिसाब दूसरा है। वह अपनी क्षमताओं को छुपाने और गैर-परंपरागत तरीके से विरोधी को झुकाने की कोशिश करता है, उन्हें स्पॉन्सर करता है। अगर हैकर्स ने काम कर दिया, तो वह कह देगा कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं। वैसे भी इंटरनेट का संसार इतना बड़ा है कि कौन कहां बैठकर क्या कर रहा है, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन क्षमता तो भारत के पास भी

कम नहीं।

वुहान लैब में जो साजिश हुई, उसका खुलासा भारतीयों ने यहां से बैठे-बैठे कर दिया। लेकिन अभी तक इस बात पर कोई चर्चा नहीं हुई कि इस क्षमता का इस्तेमाल करना कैसे है। पॉलिसी एरिया में सायबर वॉर पर बहुत कम चीजें मिलेंगी आपको। हमारी सेना भी अभी उतनी ट्रेड नहीं है। कुछ बदलाव हुए जरूर, लेकिन चीन बहुत आगे है। हमने भारत सहित पश्चिमी देशों पर होने वाले सायबर अटैक देखे हैं, तो मानना पड़ेगा कि हमारी आक्रमण क्षमता बेहद कम है।

ऐसे में एक रास्ता यह भी निकलता है कि पश्चिमी देशों की मदद ली जाए। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस तो हैं ही, इस्राइल भी माहिर है इसमें। इस्राइल से सीखने वाली बात है कि वह सायबर हमले भी करता है। हमने ईरान में देखा कि वहां कुछ संस्थाओं पर बड़े सायबर हमले हुए। इसके पीछे इस्राइल का ही हाथ माना जाता है। इसका मतलब हुआ कि वह रक्षा करना जानता है और हमला करना भी। पश्चिमी देशों में अमेरिका से सीखना होगा कि किस तरह से ओपन सोसायटी की सुरक्षा की जाए।

गलवान की घटना के बाद होने वाले हमलों को देखें, तो यह मानना गलत नहीं होगा कि हमारी जितनी संस्थाएं हैं, वे हैकिंग का शिकार हो रही हैं। भारत को इस सच्चाई को स्वीकार करके पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हम एक खुली सोसायटी हैं। यहां लोकतंत्र है।

सूचीक ववाल- 5347		उत्तिना	
1	6	7	6
2	3	9	8
6	8	3	5
1	7	1	3
5	2	6	9

अपना ब्लॉग

नेत्र' ही आडवाणी थे मोहन। वाजपेयी के लिए फिल्म मनोरंजन का साधन थी, लेकिन आडवाणी के लिए जुनून थी। 1960 में ऑर्गनाइजर के संपादक केआर मलकानी ने पत्रिका के लिए आडवाणी को कुछ फिल्मों की समीक्षा लिखने को कहा। वह 'नेत्र' नाम से हिंदी फिल्मों की समीक्षा करते, लेकिन यहां भी राजनीति पहुंच गई। 'नेत्र' ने नेहरू द्वारा ब्रिटिश फिल्म निर्माता रिचर्ड एटनबरो को गांधी के जीवन पर फिल्म बनाने के प्रयासों के लिए प्रोत्साहित किए जाने पर अपनी असहमति जताई। (1982 में आई इस फिल्म को आठ ऑस्कर पुरस्कार मिले थे) नेत्र ने इसे भारतीय फिल्मकारों की उपेक्षा के रूप में देखा। पहली बार आडवाणी को हर महीने 350 रुपये वेतन मिल रहा था। पत्रकारों के कोटे के अंतर्गत आडवाणी को आरके पुरम में एक छोटा घर भी आवंटित हुआ। 13 साल पहले कराची में अपना बंगला छोड़ने के बाद यह आडवाणी का पहला असली ठिकाना था।

पहली बार दुनिया की टॉप-300 यूनिवर्सिटी में भारत की एक भी नहीं।

इसीलिए, हम युवाओं को पकौड़े तलने की ट्रेनिंग दे रहे हैं...

